भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3362

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 अगस्त, 2021 /18 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

विमुद्रीकरण का प्रभाव

3362. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने व्यवसाय, रोजगार, कृषि और गरीबी पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो व्यवसायों, रोजगार और गरीबी उपशमन की पहलों पर इसके प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पुराने करेंसी नोटों के बदले में सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विमुद्रीकरण के बाद कोई अध्ययन किया गया है या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): किसी देश की आर्थिक समृद्धि संरचनागत, बाह्य, राजकोषीय तथा मौद्रिक घटकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करती है। अतः, अन्य घटकों को छोड़कर अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन कठिन है। आरबीआई ने मार्च, 2017 में "विमुद्रीकरण का वृहद आर्थिक प्रभाव - एक प्रारंभिक आकलन" नामक अध्ययन प्रकाशित किया है जो आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है, कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है और ऐसे खातों में जमा राशि भी बढ़ गई हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम डिजिटल लेनदेन के उपयोग में वृद्धि होना है। इस अध्ययन में बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन में अभिवृद्धि के इन दो रूझानों से भ्रष्टाचार कम करने, वित्तीय सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि करने और अर्थव्यवस्था के उच्चतर औपचारीकरण को लाभ पहुंचता है। जहां तक समग्र राशि के विनिमय का संबंध है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 15,31,094 करोड़ रुपये (पूर्णांक) की धनराशि 31 मार्च, 2021 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में चुकता कर दी गई है।

******